



द बगि पकिचर : बैंकों के बढ़ते एनपीए की समस्या

संदर्भ

रज़िर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट तथा घरेलू रेटिंग एजेंसी 'केयर रेटिंग्स' और क्रिसिलि की हालिया रिपोर्टों में देश की अर्थव्यवस्था के मॉडल और सरकार की आर्थिक नीतियों पर चर्चा जताने के साथ-साथ बैंकों, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बढ़ते एनपीए पर चर्चा जताई गई है।

पृष्ठभूमि

सुरसा के मुँह की तरह बढ़ते जा रहे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बढ़ते एनपीए के लिये रज़िर्व बैंक ने इसका बड़ा कारण परियोजनाओं के लिये कर्ज़ देते समय उनकी ठीक से जांच-परख नहीं करने के लिये मर्चेंट (नविश) बैंकों के बीच हतियों के टकराव को बताया।

रज़िर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट

- रज़िर्व बैंक की इस रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक और नज़ी क्षेत्रों के बैंकों का एनपीए चालू वित्त वर्ष की दूसरी तमाही (30 सितंबर) के अंत तक लगभग 7.34 लाख करोड़ रुपये पर पहुँच गया।
- नज़ी बैंकों का एनपीए इसी अवधि में अपेक्षाकृत काफी कम लगभग 1.03 लाख करोड़ रुपये रहा।
- गैर-नष्पादित आस्तियों (Non-Performing Assets-NPA) के मामले में कुल कर्ज़ के 10 प्रतिशत से अधिक के अनुपात के साथ ब्रिक्स देशों में भारत शीर्ष पर है।
- बैंकों के सर्वाधिक एनपीए स्तर के मामले में विश्व में भारत का पाँचवाँ स्थान है।
- इसमें सबसे अधिक योगदान कॉर्पोरेट क्षेत्र के डफाल्टों का रहा और इसमें लगभग 77 प्रतिशत हिससेदारी शीर्ष औद्योगिक घरानों के पास फंसे कर्ज़ का है।
- इस साल सितंबर तमाही में सकल एनपीए छह माह पहले के कुल कर्ज़ के 9.6 प्रतिशत से बढ़कर 10.2 प्रतिशत पर पहुँच गया।
- बैंकों के कुल एनपीए अनुपात में 19.3 प्रतिशत वृद्धि हुई है और इसमें सबसे ज्यादा हिससेदारी धातु, बजिली, इंजीनियरिंग, बुनियादी ढांचा और निर्माण क्षेत्रों की है।

ये हैं सबसे बड़े कारक: बेसकि धातुओं और धातु उत्पादों के क्षेत्र का सकल एनपीए में 44.5 प्रतिशत हिससा रहा है, जबकि निर्माण क्षेत्र का 26.7 प्रतिशत, ढांचागत क्षेत्र का 19.6 प्रतिशत और इंजीनियरिंग क्षेत्र का सकल एनपीए बढ़कर 31 प्रतिशत तक पहुँच गया। इन सभी में परियोजना मूल्यांकन भी शामिल है।

- रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि मार्च तमाही तक बैंकों का कुल एनपीए 10.8 प्रतिशत तक पहुँच सकता है और सितंबर 2018 तक यह 11.1 प्रतिशत हो सकता है।
- कुल एनपीए में इस वृद्धि में नज़ी क्षेत्र के बैंक भी शामिल हैं, जो अपनी बैलेंस शीट को मज़बूत दिखाने के लिये फंसे कर्ज़ के आँकड़े को कम करके बताते रहे हैं।

पुख्ता जाँच नहीं हुई: रिपोर्ट में रज़िर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों में एनपीए का जो संकट खड़ा हुआ है, उससे दीर्घावधि परियोजनाओं के लिये कर्ज़ देते समय उनकी जांच-परख में खामियाँ उजागर हुई हैं। इस तरह की परियोजनाओं में बैंकों के समूह ने ऋण देने की मंजूरी पेशेवर मर्चेंट बैंकों से सलाह-मशवरा करके दी है और इसमें पहले से ही हतियों का टकराव शामिल है, क्योंकि आकलन करने वाले मर्चेंट बैंकों को ऋण लेने वाले पहले से भारी भुगतान कर देते हैं।

ये बैंक रहे सबसे आगे

- भारतीय स्टेट बैंक का एनपीए सर्वाधिक 1.86 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक 57,630 करोड़ रुपये, बैंक ऑफ इंडिया 49,307 करोड़ रुपये, बैंक ऑफ बड़ौदा 46,307 करोड़ रुपये, केनरा बैंक 39,164 करोड़ रुपये और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 38,286 करोड़ रुपये का स्थान रहा।
- नज़ी बैंकों में आईसीआईसीआई बैंक 44,237 करोड़ रुपये के एनपीए के साथ शीर्ष पर रहा। इसके बाद एक्ससि बैंक 22,136 करोड़ रुपये, एचडीएफसी बैंक का एनपीए 7,644 करोड़ रुपये रहा।

उल्लेखनीय है कि ऋण बाजार में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का दबदबा है और इसमें भी भारतीय स्टेट बैंक सबसे आगे है। वह इस तरह के ऋणों की मंजूरी के लिये अपनी मर्चेन्ट बैंकिंग इकाई एसबीआई कैप्स का इस्तेमाल करता है और इसकी सलाह ऋण पुनर्गठन के लिये भी लेती है।

नरसमिहन समिति

एनपीए के मामले में 1990 के पूर्व भारतीय बैंकों का रुख स्पष्ट नहीं था। बैंकों के कामकाज में पारदर्शिता लाने तथा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भारतीय बैंकों के कार्यकलाप में बदलाव लाने के इरादे से 1991 में गठित की गई एम. नरसमिहन समिति की रिपोर्ट के आधार पर एनपीए के विधि मानकों का निर्धारण 31 मार्च, 1993 को किया गया था। इसके तहत ऋण खातों में यदि दो तमिही (180 दिनों) तक ब्याज व कसित या फरि दोनों जमा नहीं होने पर उन्हें एनपीए में बदल दिया जाता था। इसके बाद 1995 में एनपीए मानकों को और कठोर बनाया गया, जिनके तहत किसी खाते में 90 दिनों तक ब्याज या कसित या फरि दोनों तरह की रकम जमा न होने पर उसका वर्गीकरण एनपीए के रूप में किया जाने लगा।

(टीम दृष्टि इनपुट)

60 साल के न्यूनतम स्तर पर क्रेडिट ग्रोथ

एनपीए के बढ़ते बोझ से बेहाल सरकारी बैंक ऋण देने में सावधानी बरत रहे हैं। रज़िर्व बैंक की ओर से जारी आँकड़ों से पता चलता है कि एनपीए के ऊँचे स्तर के अलावा कमज़ोर कॉरपोरेट मांग के चलते देश में क्रेडिट ग्रोथ 60 साल के नचिले स्तर पर आ गई है। बीते वित्त वर्ष 2016-17 में बैंकों की ओर से कर्ज़ देने की यह रफ़्तार गरिकर केवल पांच प्रतशित रह गई। इससे पहले कर्ज़ वृद्धि की न्यूनतम दर 1953-54 में रिकॉर्ड की गई थी, तब यह केवल 1.7 प्रतशित थी। इन आंकड़ों के अनुसार बीते वित्त वर्ष में 31 मार्च, 2017 तक बैंकों की ओर से दिया गया कुल कर्ज़ 78.82 लाख करोड़ रुपए था। इसमें से 3.16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज़ मार्च के अंतमि 15 दिनों में बांटा गया।

रोज़गार वहीन विकास का खतरा

- घरेलू रेटिंग एजेंसी **केयर रेटिंग्स** ने देश में रोज़गार वहीन वृद्धि की आशंका जताई है। इसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि रोज़गार के अवसर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के अनुरूप नहीं बढ़ रहे हैं, जो चिंता का एक प्रमुख कारण है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने भी रोज़गार में कम वृद्धि की बात स्वीकार की है और इसके लिये कार्यबल का गठन किया है।
- रोज़गार वहीन वृद्धि ऐसी स्थिति है जहां अर्थव्यवस्था नरमी से तो उबरती है, लेकिन रोज़गार के क्षेत्र में स्थिति जिस-की-तस बनी रहती है।
- एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि क्षेत्रवार आधार पर सेवा क्षेत्र ने कुछ राहत दी है, लेकिन हाल में वनिरिमाण क्षेत्र रोज़गार सृजन में वफिल रहा है।
- बैंक, आईटी, खुदरा और स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार रोज़गार सृजति हो रहे हैं और आगे भी होंगे, जबकि खनिन, बजिली और दूरसंचार क्षेत्र में रोज़गार में कमी दर्ज़ की गई है।

बैंकों का पुनर्रूपीकरण (री-कैपिटलाइजेशन)

सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बढ़े फंसे कर्ज़ से जूझ रही है और उन्हें मज़बूत करने के लिये उनमें भारी मात्रा में पूंजी डाल रही है। हाल ही में अर्थव्यवस्था को गति देने, रोज़गार सृजन और बैंकिंग तंत्र को मज़बूत बनाने के उद्देश्य से सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 2 लाख 11 हज़ार करोड़ रुपए की पूंजी उपलब्ध कराने का नरिणय लिया। केंद्र द्वारा संकटग्रस्त सरकारी बैंकों के पुनर्रूपीकरण से बैंकों को एनपीए के दुष्कर से उबरने में सहायता मिलेगी। पछिले दो सालों में भारत की कमज़ोर पड़ रही अर्थव्यवस्था में नई जान फूँकने और इसकी गतिशीलता को बनाए रखने के लिये सरकार परयासरत है और इन्हीं परयासों के तहत वमिद्रीकरण और जीएसटी लागू करने के फैसले लिये गए हैं।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार की प्रवृत्तियों दखिनी आरंभ हो गई हैं और ऐसे में भारत को भी आर्थिक विकास के मोरचे पर बेहतर प्रदर्शन करना होगा। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये नविश होना चाहिये, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की खस्ता हालत को देखते ऐसा होने की संभावनाएँ अत्यंत ही कम हैं। अतः बैंकों में पूंजी डालना अनविरय हो गया। यह इसलिये भी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि कॉरपोरेट क्षेत्र की बैलेंस शीट से एनपीए बढ़ता है। अतः एनपीए की इस समस्या के समाधान हेतु कॉरपोरेट बैलेंस शीट के प्रभाव को कम करना बेहद है।

समस्या भी हो सकती है: बैंकों को पूंजी उपलब्ध कराने का नरिणय नशिचति ही सराहनीय है, लेकिन आज एनपीए चिंताजनक स्तर तक बढ़ चुका है। यदि अर्थव्यवस्था को एक जहाज़ माना जाए तो एनपीए इस जहाज़ में हो चुके छेद के समान है। अब पुनर्रूपीकरण रूपी पंप से जतिना पानी उलीच कर बाहर फेंका जाएगा, यदि उतना ही पानी यदि एनपीए रूपी छेद से फरि अंदर आता जाएगा तो पुनर्रूपीकरण के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकेगी।

इसके अलावा नई पूंजी के आवंटन की प्रासंगिकता इस बात पर भी नरिभर होगी कि बैंक इसका इस्तेमाल कतिने प्रभावी ढंग से कर रहे हैं और एनपीए से कैसे नपिट रहे हैं। भारी पैमाने पर किया जाने वाला पुनर्रूपीकरण सरकारी बैंकों को ऋण संबंधी चुनौतियों से नपिटने में मदद तो करेगा, लेकिन इससे बैंकों में सरकारी हसिसेदारी और ज़्यादा बढ़ेगी, जबकि सरकार इसे कम करना चाहती है।

(टीम दृष्टि इनपुट)

कारपोरेट क्षेत्र में रोज़गार की स्थिति का अध्ययन: केयर रेटिंग्स एजेंसी ने पछिले पांच साल के लिये कारपोरेट क्षेत्र में रोज़गार की स्थिति का भी अध्ययन किया है।

- इस अध्ययन के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 में कुल 1473 कंपनियों में 51.8 लाख रोजगार सृजति हुए जो 2014-15 में 50.1 लाख थे ।
- रोजगार में प्रतवर्ष एक प्रतशित से अधिक की वृद्धि हुई, जबकि वृद्धि दर लगभग 7 प्रतशित रही ।
- रोजगार सृजन के मामले में बैंकिंग क्षेत्र सबसे आगे रहा और रोजगार सृजन में इसका हिसा 21.3 प्रतशित रहा । इसके बाद क्रमशः आईटी, खनन, स्वास्थ्य और कपड़ा क्षेत्र का स्थान रहा ।
- वित्त वर्ष 2016-17 में जनि क्षेत्रों में रोजगार में कमी दर्ज की गयी, उसमें एफएमसीजी (रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुएँ) बनाने वाली कंपनियाँ, मीडिया और मनोरंजन तथा कागज़ क्षेत्र शामिल हैं ।

शिक्षा ऋण में भी बढ़ रहा एनपीए

- बैंकों के लिये शिक्षा ऋण भी अब समस्या बनता जा रहा है, जो मार्च 2017 में कुल का एनपीए का 7.67 प्रतशित हो गया, यह दो साल पहले 5.7 प्रतशित था ।
- भारतीय बैंक संघ के आँकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 के अंत में कुल शिक्षा ऋण 67,678.50 करोड़ रुपये पहुँच गया, जिसमें से 5,191.72 करोड़ रुपये एनपीए हो गया ।
- वित्त वर्ष 2014-15 में एनपीए 5.7 प्रतशित थी जो 2015-16 में 7.3 प्रतशित तथा पछिले वित्त वर्ष में 7.67 प्रतशित पहुँच गया ।

योजना में कया गया था बदलाव: उल्लेखनीय है कि सरकार ने कुछ समय पूर्व शिक्षा ऋण योजना के मॉडल में इसके तहत जो बदलाव किये गए, उसमें भुगतान की अवधि बढ़ाकर 15 साल करना तथा 7.5 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण के लिये **क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन लोन** की शुरुआत शामिल है, जो कर्ज़ में चूक होने पर 75 प्रतशित की गारंटी उपलब्ध कराता है ।

उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार शिक्षा ऋण के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक का एनपीए मार्च 2017 के अंत में सर्वाधिक 671.37 करोड़ रुपये रहा. उसके बाद क्रमशः एसबीआई 538.17 करोड़ रुपये तथा पंजाब नेशनल बैंक 478.03 करोड़ रुपये का स्थान रहा ।

(टीम दृष्टि इनपुट)

क्या कया जा रहा है?

- **5/25 योजना:** इसके तहत ऋण परशोधन की अवधि को 25 वर्षों तक बढ़ा दिया जाता है एवं प्रत्येक 5 वर्षों की अवधि के पश्चात् ब्याज दरों को पुनः परिवर्तित करने का प्रावधान कया जाता है ।
- **एस.डी.आर. (Strategic Debt Restructuring)**— इसके अन्तर्गत बैंक एनपीए से संबंधित कंपनियों को दिये गए ऋण को इक्विटी में बदलकर उसके प्रबंधन पर नियंत्रण कर सकते हैं, साथ ही बैंक 18 महीनों के अंदर इक्विटी को बेचकर अपने पैसे वापस ले सकते हैं ।
- **एस.4 ए:** जून, 2016 में इसे (Scheme of Sustainable Structuring of Stressed Assets-S4A) लागू कया गया, जिसके अनुसार बैंक अपने द्वारा दिये गए ऋण की कुल मात्र को सतत् (Sustainable) एवं असतत् (Unsustainable) में बाँटकर नपिटान करता है ।
- **पुनर्गठन (Restructuring):** यदि किसी कंपनी की समस्या में सुधार नहीं हो रहा है और बैंक को यह पता है कि कंपनी जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही यानी वलिफुल डिफॉल्टर नहीं है और न ही कंपनी ऋण को किसी और प्रयोजन में खर्च कर रही है, तब ऐसी स्थिति में बैंक कंपनी द्वारा लिये गए ऋण को पुनर्गठित कर सकती है, जिसके लिये ब्याज दर घटाकर ऋण चुकाने की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

प्रतभूति हति प्रवर्तन एवं ऋणों की वसूली के कानून एवं विधि प्रावधान (संशोधन) कानून, 2016

इस कानून के तहत बैंकों को ऋण अदायगी नहीं किये जाने पर गरिबी रखी गई संपत्ति को कब्ज़े में लेने का अधिकार दिया गया है । खेती की ज़मीन को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है । शिक्षा ऋण की अदायगी में हुई चूक को बटटे खाते में नहीं डाला जाएगा तथा इसकी वसूली के 'सहानुभूति का दृष्टिकोण' अपनाया जाएगा । उपरोक्त कानून के ज़रिये चार मौजूदा कानूनों--प्रतभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन एवं प्रतभूति हति प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी कानून), ऋण वसूली न्यायाधिकरण अधिनियम 1993, भारतीय स्टॉप शुल्क अधिनियम 1899 और डिपॉजिटरी अधिनियम 1996 के कुछ प्रावधानों में संशोधन किये गए हैं ताकि ऋण वसूली की व्यवस्था को और कारगर बनाया जा सके ।

(टीम दृष्टि इनपुट)

अचानक उत्पन्न नहीं हुई यह समस्या

रज़िर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के कार्यकाल में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एनपीए को नियंत्रित करने की पहल की गई थी । उन्होंने बैंकों को विश कया कि वे अपने कुल कर्ज़ में एनपीए के वास्तविक आँकड़े को सामने रखें, जो तब तक उनकी बैलेंस शीट से बाहर नहीं आ पाता था । बैंकों की सेहत सुधारने की इस कवायद के तहत बैंकों से मार्च, 2017 तक अपनी बैलेंस शीट सुधारने को कहा गया था । तब यह भी कहा गया था कि बैंकों को क्रेडिट ग्रोथ की जगह एनपीए कम करने की तरफ ध्यान देना चाहिये, क्योंकि एनपीए पर काबू पाने के बाद बैंक अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए नरिणय लेने में समर्थ हो सकते हैं ।

नष्कर्ष: भारत की बैंकिंग प्रणाली ऐसी चुनौती भरी पृष्ठभूमि में अपेक्षाकृत लंबे समय से कार्य कर रही है जिसके कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की आसता गुणवत्ता, पूंजी पर्याप्तता तथा लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । इनके मद्देनज़र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में वैश्विक जोखिम मानदंडों के अनुरूप उनकी पूंजी ज़रूरतों को पूरा करने और क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिये पूंजी लगा रही है । लेकिन एनपीए का स्तर 7 लाख करोड़ रुप से अधिक हो

जाने के कारण चिंता होना स्वाभाविक है, क्योंकि इतनी बड़ी राशिकिसी काम की नहीं है। यदि इस राशिकी वसूली हो जाती है तो सरकारी बैंकों की लाभप्रदता में इजाफा, लाखों लोगों को रोज़गार, नीतगित दर में कटौती का लाभ कारोबारियों तक पहुँचना, आधारभूत संरचना का नरिमाण, कृषिकी बेहतरी, अर्थव्यवस्था को मजबूती, विकास को गति देना आदि संभव हो सकेगा। यह भी स्पष्ट है कि एनपीए को कम करने का उपाय उसके मरज़ में छपिा है। बैंक में व्याप्त अंदरूनी तथा अन्य खामियों का इलाज, बैंक के कार्यकलापों में बेवजह दखलदाज़ी पर रोक, मानव संसाधन में बढ़ोतरी आदिकी मदद से बढ़ते एनपीए पर नशिचति रूप से काबू पाया जा सकता है।

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/problem-of-increasing-npa-of-banks>

